

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक 14 जून, 2012

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं०-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर के "भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था" योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं०-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्रांक नि-1797/3-4(जिला योजना) दिनांक 19 मई, 2012 तथा राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या-395/288-रा०यो०आ०/वा०जि०यो०/2011-12 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर "भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था" योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिये 04 माह के लेखानुदान के सापेक्ष ₹ 63,33,000/- (₹ तिरैसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनाएँ एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी०एम०-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. बी०एम०-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

क्रमशः...2

6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
 7. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 8. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
 9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
 10. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा।
 11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1206271303 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
 13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-395/288/रा०यो०आ०/वा०जि०यो०/2011-12 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 द्वारा निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91- जिला सेक्टर योजना 02-भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था हेतु संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामें डाला जाएगा।
- 3- ये आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-1) के शासनादेश सं०-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः...3

ख्या- 1172(1)/X-2-2012, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून.
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(सुशान्त पटनायक)
अपर सचिव


कमरा:-4

शासनादेश सं०- 1172 /X-2-2012-12(53)/2012, दिनांक 14 जून, 2012 का संलग्नक:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम			
		भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था			
		मानक मद			
		25- लघु निर्माण कार्य	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	योग
1	नैनीताल	73	5	61	230
2	ऊधमसिंह नगर	0	4	244	248
3	अल्मोड़ा	268	34	274	857
4	बागेश्वर	62	0	135	871
5	पिथौरागढ़	272	4	59	979
6	चम्पावत	70	42	317	1637
7	देहरादून	0	21	897	918
8	टिहरी	16	8	16	295
9	पौड़ी गढ़वाल	706	78	231	4195
10	चमोली	151	24	217	946
11	रूद्रप्रयाग	159	37	50	337
12	उत्तरकाशी	613	68	533	1214
13	हरिद्वार	277	8	299	806
	योग	2667	333	3333	6333

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹तिरेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)


(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 2406018009102

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1206271303

आवंटन पत्र दिनांक - 13-Jun-2012

पेखा शीर्षक - 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन
800 - अन्य व्यय
02 - भवन निर्माण एवं बिजली पा

01 - वानिकी

91 - जिला सेक्टर योजना

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघु निर्माण कार्य	0	2667000	2667000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	333000	333000
29 - अनुरक्षण	0	3333000	3333000
	0	6333000	6333000